त्योहारी सीज़न में कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं

मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद वैर थानाधिकारी निलंबित, 6 अधिकारी एपीओ, 2 को हटाया

जयपुर, 13 अक्टूबर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश में विगत दिनों हुई आपराधिक घटनाओं तथा कुछ पुलिस कार्मिकों की लापरवाही और अमर्यादित व्यवहार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के साथ एक्शन लिया है। उन्होंने इन घटनाओं पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित पुलिस अधिकारियों एवं कार्मिकों को तुरंत हटाने तथा उनके विरुद्ध नियमानुसार सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश

- मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने निर्देश दिए कि खनन और भूमि से जुड़े विवादों की जिलेवार विस्तृत सूची तैयार की जाए और उनके निस्तारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्यवाही की जाए।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को कानून व्यवस्था की उच्चस्तरीय बैठक ली।

दिए। मुख्यमंत्री ने पुलिस महानिदेशक सहित, बैठक में मौजूद पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि खनन एवं भूमि से जुड़े विवादों की जिलेवार विस्तृत सूची तैयार की जाए और उनके निस्तारण के लिए प्रभावी कार्ययोजना बनाकर कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रदेश में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है एवं राज्य सरकार माफियाओं के किसी भी तरह के अपराध को बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि माफियाओं पर पूरी तरह से शिकंजा कसा जाए। साथ ही, आपराधिक घटनाओं एवं पुलिस के आचरण से संबंधित प्रकरणों की गहन समीक्षा की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारी सीजन को देखते हुए कानून एवं यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। हर छोटी से छोटी घटना पर संबंधित पुलिस अधिकारी संज्ञान ले, ताकि बड़ी घटनाओं को होने से रोका जा सके। साथ ही, सभी अधिकारी अपने प्रभार वाले रेंज-जिलों में कानून व्यवस्था की नियमित समीक्षा करें। उन्होंने महिला सुरक्षा के लिए "कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स" का सुचारू एवं सुव्यवस्थित संचालन तथा स्कूल कॉलेजों में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट्स के इंटरएक्शन सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए, ताकि महिला अपराधों पर प्रभावी रोकथाम लगाई जा सके। बैठक के बाद, पुलिस विभाग द्वारा 1 अधिकारी को निलंबित, 6 अधिकारियों को एपीओ किया गया एवं 2 अधिकारियों को तुरंत हटाया गया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में, वैर के थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह को निलंबित एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेरणा शेखावत को पदस्थापन की प्रतीक्षा में रखा गया है। इसी तरह वृत्ताधिकारी भुसावर नीरज भारद्वाज, उपपुलिस अधीक्षक (यातायात) अजमेर अंजू यादव, वृत्ताधिकारी सांभर मुकेश जोशी तथा वृत्ताधिकारी श्रीगंगानगर विष्णु कुमार खत्री तथा पुलिस निरीक्षक, आयुक्तालय जयपुर के मुकेश खराड़िया को भी एपीओ किया गया है। इसके अलावा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसआईयूसीएडब्ल्यू, जयपुर ग्रामीण बृजमोहन मीणा तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, खैरथल जया सिंह को हटाया गया है।

बैठक में पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) भास्कर ए. सावंत सहित, अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।

अब ईडी ने भगवंत मान के ओएसडी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की

चंडीगढ़ , 13 अक्टूबर। प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुम्मन के खिलाफ बुधवार को जालंधर में मामला दर्ज किया है। एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की एफआईआर पर राजबीर घुम्मन की गिरफ्तारी और किसी भी तरह की सख्त

- एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ओएसडी पर सीबीआई की एफआईआर पर दंडात्मक कार्यवाही पर रोक लगाई थी।

दंडात्मक कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट की राहत के बाद अब ईडी ने मामला दर्ज कर लिया है।

ईडी की इस एफआईआर ने न केवल जांच का दायरा बढ़ा दिया है, बल्कि पंजाब की राजनीति में भी गर्माहट ला दी है। विपक्षी दल इस मामले को लेकर सरकार पर हमलावर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष इस पूरी स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है। अब सभी की निगाहें ईडी की आगामी कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।

ईडी ने अगस्त में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव को 3 पत्र भेजकर सीएम ऑफिस से जुड़े कथित भ्रष्टाचार पर एफआईआर की मांग की थी, जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर, सीएलयू और अन्य सरकारी मंजूरियों में कथित दखल के आरोप लगे थे। ईडी के मुताबिक नितिन गोहल, राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों की भूमिका सामने आई। एजेंसी ने गोहल को सरकारी काम कराने के इच्छुक लोगों और सीएम के ओएसडी घुम्मन के बीच कथित बिचौलिया बताया।

रावला मंडी के पास पाकिस्तान ने विस्फोटक हथियार गिराए

सात किलो विस्फोटक, दो पिस्टल, चार मैगज़ीन, 650 कारतूस बरामद, दो युवक गिरफ्तार

अनूपगढ़, 13 अक्टूबर। पाकिस्तान बॉर्डर से सटे श्रीगंगानगर जिले के रावला मंडी क्षेत्र में भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक सामग्री पकड़ी गई है। इनमें 7 किलोग्राम विस्फोटक, दो जिगाना पिस्टल, चार मैगजीन और करीब 650 कारतूस हैं। चार जोड़ी बैटरी और दो रिमोट भी हैं। ये हथियार देर रात पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए गिराए गए। आशंका है कि यह किसी बड़ी साजिश की तैयारी थी।

- सोमवार रात 12 से 2 बजे के बीच पाकिस्तानी ड्रोन से ड्रॉपिंग हुई। खानुवाली पोस्ट से करीब एक किलोमीटर दूर नहर किनारे एक खेत में तीन पैकेट बरामद हुए। सीमा से सटे खेतों, नहर किनारे व आसपास के क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

इनपुट मिलने पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और रावला पुलिस ने ग्राम पंचायत 12 केएनडी के गांव चक 4 केएनएमडब्ल्यू टेल के पास कार्रवाई की। इस मामले में पंजाब निवासी दो युवकों को गिरफ्तार किया गया है।

कार्रवाई के बाद सीमा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। सर्च ऑपरेशन जारी है। विस्फोटक की जांच के लिए जयपुर से एंटी बम स्क्वाड को बुलाया गया है। एएनटीएफ के आईजी विकास कुमार ने बताया, ड्रोन की मदद से राजस्थान में भारी मात्रा में गोला-बारूद और विस्फोटक गिराए गए हैं। इस सामग्री को भेजने वाले लोग कौन हैं और उनका उद्देश्य क्या था, इसकी जांच जारी है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की जांच कर रही हैं और धीरे-धीरे सभी तथ्य सामने आएंगे। दो आरोपी पकड़े गये हैं।

एएनटीएफ कॉन्स्टेबल अवतार सिंह ने बताया कि सोमवार रात करीब 12 से 2 बजे के बीच पाकिस्तानी ड्रोन से ड्रॉपिंग हुई। 12 केएनडी के गांव चक 4 केएनएमब्ल्यू टेल के पास पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए, खानुवाली पोस्ट से करीब एक किलोमीटर दूर नहर किनारे एक खेत में तीन पैकेट गिराए गए। एएनटीएफ को अलसुबह 3 बजे इसकी सूचना मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। मौके से कुल तीन पैकेट मिले हैं। इनमें से दो पैकेट में 2 जिगाना पिस्टल, 4 मैगजीन और करीब 650 कारतूस बरामद हुए हैं। पिस्टल पर मेड इन टर्की लिखा हुआ है। तीसरे पैकेट में विस्फोटक सामग्री है।

घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। सीमा से सटे खेतों, नहर किनारे और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। संदिग्धों से पूछताछ कर उनके सम्पर्कोंऔर इस मामले से जुड़े अन्य पहलुओं की जानकारी जुटाई जा रही है।

एएनटीएफ के सीआई महेन्द्र दत्त शर्मा, रावला थाना प्रभारी बलवंत कुमार, बीएसएफ के महेश, सीआईडी की एएसपी दीक्षा कामरा और एटीएस के सीआई हनुमाना राम बिश्नोई मामले की जांच कर रहे हैं। सुरक्षा एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि हथियारों और विस्फोटक की खेप कहां पहुंचाई जानी थी। इसके पीछे कौन लोग शामिल हैं। सीमा क्षेत्र में नाकाबंदी के साथ तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मामले में आगे और खुलासे होने की संभावना है।

यूपीआई लेन-देन ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

फिलहाल टाल दिया गया है और इसे दीपावली के बाद लागू किया जाएगा, जिसकी तारीख अलग से बताई जाएगी। स्टीयरिंग कमेटी ने जारी बयान में बताया कि उद्योग जगत, वाणिज्यिक संगठनों, फिनटेक कंपनियों और पेमेंट एग्रीगेटरों के द्वारा नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) और वित्त मंत्रालय के सामने उठाई गई चिंताओं के बाद इस समयसीमा को बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया गया है। दशहरा, दिवाली और छठ की बंपर खरीदारी के बीच कारोबारियों और आम जनता को राहत देते हुए इस नियम को दिवाली के बाद तक के लिए टाल दिया गया है।

बिहार : बच्चों से भरी नाव नदी में डूबी, 11 मासूमों की मौत

एक छोटी नाव पर 15 से 20 बच्चे भोज खाने के लिये जा रहे थे

वैशाली, 13 अक्टूबर। राघोपुर थाना क्षेत्र के रामपुर श्यामचंद पंचायत में मंगलवार की रात्रि नाव हादसे में 11 बच्चों की डूबने से मौत हो गई।

मौत की सूचना पर गांव में कोहराम मच गया। सभी की उम्र लगभग 10 से 15 साल के बीच थी। शवों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राघोपुर में रखा गया है।

जानकारी के अनुसार, रामपुर श्यामचंद पंचायत के भगतान टोला स्थित माता महारानी स्थान के निकट सिंघेश्वर राय के यहां भोज था। एक छोटी नाव पर करीब 15 से 20 बच्चे सवार होकर भोज खाने के लिए ढ ाब के उस तरफ जा रहे थे।

- स्थानीय लोगों की मदद से घंटे भर की मशक्कत के बाद कई बच्चों को बाहर निकाला गया और प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र राघोपुर फतेहपुर पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने जांच के बाद 11 बच्चों को मृत घोषित किया।

इसी दौरान बीच ढ ाब में नाव डूब गई। नाव डूबने की सूचना पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना मिलते ही रामपुर श्यामचंद पंचायत के लोग एवं आसपास के गांव के लोग घटनास्थल पर जुट गए।

स्थानीय लोगों की मदद से घंटे भर की मशक्कत के बाद कई बच्चों को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को आनन-फानन में इलाज के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राघोपुर फतेहपुर पहुंचाया गया।

रामपुर श्यामचंद में नाव हादसे के बाद स्थानीय लोग पानी में डूबे लोगों को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राघोपुर फतेहपुर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद 11 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया।

अब 86 प्रतिशत उद्योग गंगा बेसिन में प्रदूषण मानकों का पालन करते हैं

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत गंगा बेसिन में औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के प्रयासों से निर्धारित मानकों का पालन करने वाले उद्योगों की संख्या वर्ष 2017 के 39 फीसदी से बढ़ कर 2025 में 86 फीसदी हो गई है। इस अवधि में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग (बीओडी) का भार 26 टन प्रतिदिन से घटकर 7.16 टन प्रतिदिन रह गया। औद्योगिक इकाइयों के नियमित निरीक्षण, अपशिष्ट जल शोधन व्यवस्था की निगरानी, स्वच्छ उत्पादन तकनीकों और जल पुनर्चक्रण पर जोर के जरिए प्रदूषण कम करने के प्रयास किए जा रहे हैं। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के अनुसार, नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत प्रदूषण फैलाने की अधिक आशंका वाले उद्योगों की पहचान कर उनका वार्षिक निरीक्षण किया जा रहा है।

सऊदी अरब ने हूती की मिसाइलों को हवा में रोका

हूती विद्रोहियों ने खमीस मुशैत शहर को निशाना बनाकर दो बैलिस्टिक मिसाइल दागी थीं

रियाद, 13 अक्टूबर। सऊदी अरब की वायु रक्षा प्रणाली ने ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों के देश के महत्वपूर्ण शहरों में से एक को निशाना बनाने के प्रयास को विफल कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि खमीस मुशैत शहर की तरफ दागी गई दो बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही सफलतापूर्वक रोककर तबाह कर दिया। इस घटना के बाद से स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह से सतर्क हैं।

गल्फ न्यूज, अल जजीरा और अरब न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, यमन में वैध सरकार को बहाल करने के लिए बने सऊदी-नीत गठबंधन ने इस खतरनाक हमले की पुष्टि करते हुए बताया कि मिसाइलों के हवा में नष्ट होने के कारण इनके कुछ टुकड़े आसपास की इमारतों और वाहनों पर गिरे। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी भी तरह के जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा बलों ने तुरंत मोर्चा संभालते हुए स्थिति को नियंत्रण में ले लिया और स्थिति का जायजा लिया।

- सऊदी अरब के अनुसार, हवा में नष्ट होने के बाद मिसाइलों के कुछ टुकड़े इमारतों व वाहनों पर गिरे पर किसी तरह के जान-माल का नुकसान नहीं हुआ।

खमीस मुशैत दक्षिण-पश्चिम सऊदी अरब के असिर प्रांत में स्थित एक प्रमुख शहर है। यह शहर असिर प्रांत की राजधानी आभा से लगभग 27 किलोमीटर पूर्व में स्थित है। रियाद, जेद्दा, मक्का और मदीना के बाद, यह सऊदी अरब का पांचवां सबसे बड़ा शहर माना जाता है। गठबंधन के प्रवक्ता मेजर जनरल तुर्की अल-मलिकी का कहना है कि हूती विद्रोहियों ने सोमवार आधीरात बाद यमन की सीमा से खमीस मुशैत एयरबेस की ओर दो बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं। उन्हें रोककर नष्ट कर दिया गया।

इससे पहले सऊदी नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने खमीस मुशैत के लिए संभावित खतरे के प्रति सतर्क रहने की चेतावनी जारी की थी। गठबंधन के प्रवक्ता ने इस घटनाक्रम की जानकारी एक्स पोस्ट के माध्यम से दी। गठबंधन ने सोमवार को कहा था कि वह ड्रोन और क्रूज मिसाइलों से किए गए हमले का जवाब दे रहा है। हूती ने सऊदी अरब के हवाई अड्डों और तेल ठिकानों को निशाना बनाया है।

किंग खालिद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर शनिवार को हूती हमलों में 13 लोगों की मौत हो चुकी है। बुधवार और गुरुवार को हुए हमलों में चार लोग और रविवार को एक और व्यक्ति मारा गया। सोमवार को रियाद के बाहरी इलाके में स्थित इस बड़े हवाई अड्डे पर कामकाज बंद रहा।

कोलकाता में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

इसी दौरान एक महिला ने ममता को पीसी (हुआ) कहकर पुकारा और उनकी ओर दौड़ी। डोला का आरोप है कि महिला नशे में थी और उसने ममता पर झपटने की कोशिश की।

कॉकरोच जनता पार्टी, पुलिस की चौकसी ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

आलोचना की और आरोप लगाया कि सरकार लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शनों को रोकने की कोशिश कर रही है।

एक्स पर एक पोस्ट में रमेश ने इस कदम को सरकार की राजनीतिक घबराहट का संकेत बताया।

उन्होंने लिखा, "यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी में भारी घबराहट है। ऐतिहासिक जंतर-मंतर अब वह जगह नहीं रहेगी, जहां हमारे लोकतंत्र को रोजाना मजबूती मिलती थी।"

मंगलवार को हिरासत में लिये जाने की यह घटना दिल्ली पुलिस और सीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच एक और टकराव का संकेत है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पार्टी के अभियान के चलते राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 10 अक्टूबर को दीपके, दास और रांका सहित, सीजेपी के कई नेताओं को प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले ही दिल्ली हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया था, तथा बाद में कार्यकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष कार्यवाही के बाद उन्हें रिहा कर दिया गया था।प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (स्पेशल इन्टेन्सिव रिविजन -एसआईआर) के दौरान अनियमितताओं का आरोप लगाया है और ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है। इन आरोपों पर विवाद बना हुआ है। ताजा विरोध प्रदर्शन के बाद, जंतर-मंतर का आधिकारिक प्रदर्शन स्थल का दर्जा हटाए जाने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस फैसले से उनका विरोध -प्रदर्शन नहीं रुकेगा।

थाने में पिटाई ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निलंबन काफी नहीं, अनुशासनहीन और कानून के खिलाफ काम करने वाले पुलिसवालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक व कानूनी कार्रवाई हो और जांच रिपोर्ट के आधार पर उन्हें पद से भी हटाया जाए। आयोग ने संबंधित अफसरों को नोटिस जारी कर 16 अक्टूबर को पालना रिपोर्ट के साथ पेश होने को कहा है। आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जी.आर. मूलचन्दानी की बेंच ने यह आदेश समाचार पत्रों में छपी खबर के आधार पर लिए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

जब्त वाहन की मियाद से पहले ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

निवासी याचिकाकर्ता ट्रेवल एजेंसी चलाता है। है। उसने बैंक से लोन लेकर गाड़ी खरीदी थी, जो 6 नवंबर, 2014 को चोरी हो गई। इसके बाद 25 नवंबर 2014 को अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र में इस वाहन को अवैध शराब से भरा हुआ पकड़ा। आबकारी आयुक्त, राजस्थान, उदयपुर ने 30 जून 2015 को आदेश पारित कर वाहन को जब्त कर लिया तथा याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया। याचिका में कहा गया कि राजस्थान टैक्स बोर्ड, अजमेर में अपील करने के लिए कानूनन 60 दिन की समय-सीमा पूरी होने से पहले 19 अगस्त को आबकारी विभाग ने वाहन को नीलाम कर दिया। जब याचिकाकर्ता ने वाहन की नीलामी राशि रिफंड करने का आवेदन किया, तो आबकारी विभाग ने यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया कि वह आरोपी के कोर्ट से बरी होने का आदेश पेश करे। याचिका में कहा गया कि जब याचिकाकर्ता को कभी आपराधिक मामले में आरोपी ही नहीं बनाया गया था, तो उससे बरी होने का आदेश मांगना पूरी तरह अतार्किक है।

आईएमएफ ने हिंदुस्तान ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

की मजबूती का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि कई दशकों में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था आज सबसे मजबूत स्थिति में है। उन्होंने कहा कि गुड्स एण्ड सर्विस टैक्स (जीएसटी), दिवालियापन कानून, लेबर कोड और कारोबार से जुड़े छोटे अपराधों को अपराध की श्रेणी से हटाने जैसे सुधारों का भी उल्लेख किया। उनके अनुसार, इन कदमों से भारत में निवेश आकर्षित करने और वैश्विक संकटों का सामना करने की क्षमता बढ़ रही है।

प्रधानमंत्री ने भारत के विकास मॉडल को ऐसा मॉडल बताया, जो घरेलू तरक्की और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मेल है। सस्ती दवाओं, डिजिटल पहचान और पेमैंट व्यवस्था, कुशल कामगारों तथा ग्लोबल केपबिलिटी सैंटर्स का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भारत दुनिया को नुकसान पहुँचा कर नहीं, बल्कि दुनिया के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले दस वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला गया है।

हालांकि, इस सकारात्मक नज़रिए के साथ कई बड़े जोखिम भी जुड़े हैं। आईएमएफ के अनुमानों के अनुसार, वर्ष 2026 में कच्चे तेल की औसत कीमत 95.74 डॉलर प्रति बैरल रह सकती है, जो वर्ष 2025 के औसत से लगभग 41 प्रतिशत अधिक है। पश्चिम एशिया में लंबे समय तक संघर्ष जारी रहने से ऊर्जा की कीमतें और बढ़ सकती हैं। इससे आयातित वस्तुओं की कीमतें बढ़ सकती हैं और भारत का बाहरी व्यापार घाटा भी बढ़ सकता है। आईएमएफ ने वर्ष 2026 में वैश्विक आर्थिक विकास दर केवल 3.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की नाजुक स्थिति को दर्शाता है।

भारत के सामने मुख्य चुनौती यह है कि वह मजबूत आर्थिक विकास दर को लगातार निवेश, उत्पादक रोजगार और परिवारों की बढ़ती आय में बदले। इसके साथ ही महंगाई पर नियंत्रण रखे और बाहरी आर्थिक स्थिरता बनाए रखें। आईएमएफ द्वारा विकास दर का अनुमान बढ़ाना उत्साहजनक है, लेकिन इस गति को बनाए रखना घरेलू मांग की मजबूती, ढांचागत सुधारों की रफ्तार और बाहरी आर्थिक झटकों को झेलने की भारत की क्षमता पर निर्भर करेगा।

चुनाव आयुक्तों को कानूनी कार्यवाही से छूट क्यों मिले?

छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र व चुनाव आयोग को नोटिस जारी किये

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों को उनके आधिकारिक कामकाज के लिए कानूनी कार्रवाई से मिली व्यापक छूट का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। शीर्ष अदालत ने इस छूट को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर मंगलवार को केन्द्र सरकार और भारतीय निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया।

अदालत के इस कदम से चुनाव आयुक्तों को मिली कानूनी सुरक्षा और उनकी जवाबदेही से जुड़े सवाल फिर चर्चा में आ गए हैं। याचिका में कहा गया है कि इस तरह की व्यापक छूट संवैधानिक पदों पर बैठे अधिकारियों को सामान्य कानूनी प्रक्रिया से बाहर कर सकती है।

- इस विवाद का केन्द्र वह प्रावधान है जो पद पर रह चुके या वर्तमान में कार्यरत, मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों को कर्त्तव्य निभाते समय किये कामों के लिये दीवानी और अपराधिक मुकदमों से सुरक्षा देता है।

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की याचिका पर सुनवाई करते हुए केन्द्र और निर्वाचन आयोग से जवाब मांगा। यह याचिका मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा की शर्तों और कार्यकाल से जुड़े 2023 के कानून की धारा 16 को चुनौती देती है। मामले की अगली सुनवाई दो नवंबर को होने की संभावना है।

इस विवाद का केन्द्र वह प्रावधान है, जो पद पर रह चुके या वर्तमान में कार्यरत मुख्य चुनाव आयुक्तों और चुनाव आयुक्तों को आधिकारिक कर्तव्य निभाते समय किए गए काम, कार्रवाई या कही गई बातों के लिए दीवानी और आपराधिक मुकदमों से सुरक्षा देता है।

इस प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका में इसी व्यापक सुरक्षा पर सवाल उठाया गया है। क्या यह छूट संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है? एडीआर का तर्क है कि 2023 के कानून की धारा 16, संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 का उल्लंघन करती है। याचिका के मुताबिक, इतनी व्यापक कानूनी सुरक्षा मिलने से जवाबदेही कमजोर हो सकती है और कथित मनमानी या भ्रष्टाचार के मामलों की न्यायिक जांच में बाधा आ सकती है।

एक-एक करके, केन्द्रीय ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

बी.एल. वर्मा को उनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद राज्यसभा के लिए दोबारा उम्मीदवार नहीं बनाया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री पुरी और केन्द्रीय राज्य मंत्री वर्मा उन मौजूदा सांसदों में शामिल थे, जिन्हें उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटों के लिए पार्टी की उम्मीदवारों की सूची में शामिल भी किया गया।

केन्द्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने भी केन्द्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया है। इससे पहले केन्द्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू और जॉर्ज कुरियन ने राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने और पार्टी की ओर से दोबारा नामांकन नहीं मिलने के बाद इस्तीफा दे दिया था। बिट्टू और कुरियन ने जून और जुलाई में अपने पद छोड़े थे।

लगातार हो रहे इन इस्तीफों से मंत्रिमंडल में करीब आधा दर्जन पद खाली हो गए हैं। इससे जल्द ही मंत्रिमंडल के विस्तार या फेरबदल की उम्मीदें बढ़ गई हैं। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि यह समय भाजपा की संगठनात्मक प्राथमिकताओं के अनुरुप है, जिनमें महत्वपूर्ण राज्यों में भाजपा की आगामी सक्रियता और आगामी चुनावों से पहले प्रतिनिधित्व को संतुलित करने की आवश्यकता शामिल है।

इन अटकलों को उस समय और बल मिला, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हाल के सप्ताहों में केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के साथ कई बैठकें कीं। सेवा तीर्थ परिसर सहित, विभिन्न स्थानों पर हुई इन बैठकों में मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई। इन बैठकों को मंत्रियों के प्रदर्शन और मंत्रालयों के कामकाज के व्यापक मूल्यांकन के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है।

राजनीतिक हलकों के सूत्रों के अनुसार, लंबे समय से प्रतीक्षित केन्द्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल दिवाली से पहले हो सकता है। कई मंत्री पद खाली होने और भाजपा में संगठनात्मक बदलावों, जिनमें संसदीय बोर्ड में संभावित बदलाव भी शामिल हैं, की तैयारी करने के साथ, आने वाले हफ्तों में नई नियुक्तियों और विभागों में फेरबदल को लेकर स्थिति साफ होने की उम्मीद है।

राष्ट्रदूत (एच.यू.एफ.) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, सुधर्मा, एम.आई.रोड़, जयपुर एवं सुधर्मा-II, लालकोठी शॉपिंग सेंटर, टोंक रोड़, जयपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक:- राजेश शर्मा । आर.एन.आई. नं. 3641/57, ई-मेल-rastrdut@gmail.com कोटा कार्यालय:-पलायथा हाउस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन:2386031, 2386032, फैक्स:0744-2386033 बीकानेर कार्यालय:-कुंभाना हाउस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन:2200660, फैक्स: 0151-2527371 उदयपुर कार्यालय:-आयड, मेन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, 2418945, फैक्स: 0294-2410146 अजमेर कार्यालय:-घूघरा घाटी, जयपुर रोड,अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- प्लाट नम्बर H1-4, इन्डस्ट्रीयल एरिया फैस प्रथम, जालौर, (राज.) फोन नम्बर 226422, 226423, जालौर। फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय: एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन: 256906, 256907, फैक्स:01562-256908